found in the habit of issuing false late sitting certificates to their subordinates;

(b) if so, whether the matter was investigated by the Special Police authorities; and

(c) if so, what are the findings of such inquiry?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): (a), (b) and (c). In January 1959, an anonymous complaint was received that certain Ministerial and Class IV staff in the Ministry had been wrongly allowed over-time allowances. The complaint was investigated by the Special Police Establishment and certain irregularities in the payment of over-time allowances were noticed. A scrutiny of the irregularities did not reveal any deliberate malafides. Payments which were considered irregular were, therefore, recovered.

Export of Scrap Iron

1990. Shri Chandak: Will the Minister of **Steel, Mines and Fuel** be pleased to state:

(a) whether export of scrap iron has been allowed in exchange for import of other items; and

(b) if so, what are the details as to the quantity and value of scrap iron allowed for export and destinations, and the names and values of items allowed for import in exchange thereof together with the countries of origin during the period from April, 1958 to March 1959 and from April to November, 1959?

The Minister of Steel, Mines and Fuel (Sardar Swaran Singh): (a) and (b). Since June. 1958 exports of scrap against import of steel items have been allowed. So far 1,26,000 tons of scrap valued at Rs. 2,18,40,000 has been exported mostly to Japan on barter basis. A statement containing the categories of steel items together with their values imported during April, 1958 to March 1959 and April to November 1959 is laid on the Table of the Sabha. [*See* Appendix III, annexure No. 100]. The imports of steel are being made from Japan and the continent.

ग्वालियर में प्रतिरक्षा मंत्रालय की भूमि

१९९१. श्री रा० च० शर्मा : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १६ अप्रैल, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१८७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर में प्रतिरक्षा मंत्रालय की भूमि के बारे में जानकारी इस बीच प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) मध्य प्रदेश में ग्वालियर में प्रतिरक्षा विभाग के अधिकार में जो भूमि और वन हैं उनसे कितनी वार्षिक आय होती है और उन पर कितना व्यय होता है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) (क) जी हां ।

(ख) १. मध्य प्रदेश के ग्वालियर भाग में, कृषि योग्य, उस भूमि और जंगलों का ब्योरा, जिन्हें भूतपूर्व ग्वालियर रियासत अपनी सेनाओं के प्रयोग में लाती थी, और अब रक्षा विभाग के अधीन है, इस प्रकार है :—

(१) कृषि योग्य भूमि क्षेत्र —

(२) जंगल क्षेत्र ७१,९७७ एकड़

२. राज्य सरकार ने जंगल क्षेत्र की वापसी की मांग की है । इस मांग पर विचार हो रहा है, और इस पर, रक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया जायगा ।

(ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में वार्षिक आय और व्यय का ब्योरा इस प्रकार है :—

वर्ष	आय	व्यय
	रु० न० पै०	रु० न० पै०
१९५६–५७	२४,२०२.४१	१७,७७७.७०
१९५७–५८	४६,४६४.४३	२४,२२१.१८
१९५८–५९	५३,०२९.३१	२६,४३५.३९